स्वच्छता लक्ष्यों पर प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

द हिन्दू

27 नवंबर, 2019

"अभाव के अन्य रूपों को संदर्भित किए बगैर स्वच्छता एक आदर्श साबित नहीं हो सकती।"

भारत के हाई-प्रोफाइल स्वच्छ भारत कार्यक्रम ने सभी को स्वच्छता प्रदान करने के अपने लक्ष्य के लिए विश्व स्तर पर तालियाँ बटोरी है, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नए सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, यह अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुँचा है जहाँ इसके होने के बारे में बताया जा रहा है।

देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों के घरों में शौचालय की उपस्थिति बढ़ी है लेकिन पिछले साल अक्टूबर तक लगभग 28% की कमी थी और यह स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के 5% दावे के अनुरूप भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह घोषणा कि देश ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त कर दिया है, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली थी लेकिन इस सर्वेक्षण अनुसार इस लक्ष्य पर वापस ध्यान दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कई राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था लेकिन एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार यह स्थिति अभी तक अपने लक्ष्य से पीछे है। हालाँकि, केंद्र ने सर्वेक्षण के परिणामों को गलत ठहराया है लेकिन इसे आदर्श रूप से एक नए मूल्यांकन के रूप में माना जाना चाहिए। डेटा झारखंड, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रदर्शन की समीक्षा करने में मदद कर सकता है जहाँ शौचालयों की कमी राष्ट्रीय औसत से अधिक बताई गई है।

अधिक मौलिक रूप से सर्वेक्षण शिक्षा, आवास और पानी की आपूर्ति जैसे अन्य सामाजिक निर्धारकों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है जो स्वच्छता अपनाने पर एक मजबूत प्रभाव डालते हैं। यदि समग्र अभाव के कारण समुदाय स्वच्छता के लाभों को देखने में असमर्थ हैं तो स्वच्छता को एक अलग आदर्श के रूप में आगे बढ़ाना व्यर्थ साबित होगा।

केंद्र सरकार राज्यों द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर ग्रामीण भारत पर पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) होने के अपने दावों को दोहरा रही है। जल मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा कि 5,99,963 गाँवों में कवरेज 2014 में 38.7% से बढ़कर इस साल 100% हो गया है।

Table 1. Proportion of rural households having access to toilets, by State, 2012 and 2018, NSS surveys and administrative data

States	2012 (NSS)	2018 (NSS)	2018-19 (SBM-Gramin)
Andhra Pradesh	45.7	77.4	100
Arunachal Pradesh	87.4	98.4	98.9
Assam	86.3	97.5	99.9
Bihar	27.2	63.8	97.8
Chhattisgarh	23.3	91.4	99.9
Goa	90.3	81.5	89.3
Gujarat	41.3	75.8	99.5
Haryana	74.6	95.8	99.9
Himachal Pradesh	74.3	97.3	99.9
Jammu and Kashmir	55.7	85.2	99.9
Jharkhand	9.5	58.1	99.9
Karnataka	29.2	69.9	99.9
Kerala	72.0	99.6	100
Madhya Pradesh	21.0	71.0	100
Maharashtra	46.0	78.0	99.6
Manipur	88.0	100.0	99.9
Meghalaya	55.0	98.1	100
Mizoram	93.0	100.0	99.4
Nagaland	100.0	100.0	99.7
Odisha	18.7	49.3	87.1
Punjab	77.8	93.4	99.3
Rajasthan	27.0	65.8	99.9
Sikkim	98.0	100.0	100
Tamil Nadu	33.6	62.8	99.8
Telangana	45.7	77.5	88.1
Tripura	86.0	99.3	98.4
Uttar Pradesh	24.7	52.0	99.5
Uttarakhand	80.3	97.1	99.5
West Bengal	60.3	83.7	99.9

यह निर्विवाद है कि शौचालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और इसके लिए करदाताओं को वस्तु और सेवा कर की शुरूआत तक 2015 से उपकर के रूप में लगभग 20,600 करोड़ रुपये की छूट मिली है। फिर भी यह दिखाने के लिए सबूत है कि यह हर जगह उपयोग में नहीं आया है। एनएसओ के सर्वेक्षण के परिणामों में एक नया आयाम जुड़ा है क्योंकि वे ओडीएफ पर स्वच्छ भारत अभियान द्वारा भरोसा किए गए डेटा को नकारते हैं।

भारत के गाँवों में चहुँमुखी विकास लाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का सृजन करना पड़ेगा। ग्रामीण आवास और पानी की आपूर्ति सभी के लिए शौचालय का उपयोग लाने के लिए महत्त्वपूर्ण है और एक सवाल यह है कि क्या सरकार के प्रमुख आवास कार्यक्रम के तहत् 2022 तक लक्षित 2.95 करोड़ सब्सिडी आवासों की कमी को दूर कर सकते हैं।

यह सर्वविदित है कि कुछ राज्यों में विकास सूचकांक कम है और जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है वहाँ स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक स्वच्छता लाने की क्षमता और संसाधनों की कमी है। कवरेज में समस्याओं को खत्म करने के लिए निरंतर काम और एक बड़ा शहरी कार्यक्रम खुले में शौच और सार्वभौमिक शौचालय के उपयोग को समाप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के नए सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कीजिए:

1. इस रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं, जहाँ सबकी शौचालय तक पहुँच नहीं है।
2. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 29% ग्रामीण घरों और 4% शहरी घरों में शौचालय नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements related to the new survey report of the National Statistical Office (NSO):

1. According to this report, Odisha, Uttar Pradesh, Jharkhand are the worst performing states, where not everyone has access to toilets.
2. It is found in this report that 29% rural household and 4% urban household do not have toilets

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) 1 and 2 (d) Nither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः "भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा स्वच्छ भारत मिशन को पूर्णतः सफल बनाने हेतु प्रशासनिक, नीतिगत निर्णयों से बढ़कर लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत के पक्ष को सोदाहरण दर्शाएं। (250 शब्द)

Changing the attitude of the people beyond administrative, policy decisions is necessary to make India defecation free and make the Swachh Bharat Mission a complete success. Do you agree with this statement? Present your views with appropriate examples. (250 words)

नोट : 26 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।